Power crisis in Assam

563. SHRI KRISHNA BAHADUR CHETTRI:
SHRI NABIN CHANDRA BURAGOHAIN:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Assam is facing a power crisis; and

(b) if so, what steps the Central Government are taking to avert this crisis in the State?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESWAR PRASAD): (a) and (b) Against the present unrestricted requirement of 2 million units per day, the availability in Assam State is 1.82 million units per day. In order to rationalise the distribution of the available electrical energy, certain control measures like restrictions on peak loads, ban on ostentatious illumination, advertisements etc. are in force.

The following major power schemes are under execution at present to meet the future requirements of the North-Eastern Region.

1. Loktak Hydro-electric Project (Manipur) 105 MW
2. Kyrdemkulai Hydro-electric Project (Meghalaya) 60 MW
3. Kopili Hydro-electric Project (Assam and Meghalaya) 150 MW.
4. Bongaigaon Thermal Project (Assam) 2x60 MW

मंदिरों की आय का उपयोग करने के लिए कानून बनाया जाना

564. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तरी और पूर्वी भारत के मंदिरों की आय के अधिकांश भाग का उपयोग कुछ व्यक्ति विशेष ही करते हैं ;

(ख) क्या सरकार इन मंदिरों की आय का उपयोग दक्षिण भारत के मंदिरों की निधियों की भांति आम जनता के लाभ के लिये करने के उद्देश्य से एक न्यास बनाने अथवा संसद् में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की सम्भावना है ?

†[**Legislation to provide for the use of earnings of temples**

564. SHRI PRAKASH VEER SHASTRI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a major portion of the earnings of the temples in the Northern and Eastern India is used by some individuals only; and

(b) whether Government propose to form a trust or to introduce a bill in Parliament to provide for the use of earnings on such temples for the benefit of general public as is being done in the case of the South Indian temple funds; and

(c) if so, by when a decision in this regard is likely to be taken?]

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) यह विषय अनिवार्यतः संबंधित राज्य सरकारों का है। हाल ही में मंदिरों की निधियों इत्यादि के प्रबन्ध और उपयोग को नियमित करने हेतु दक्षिण के कुछ राज्यों में इसी तरह के विधान की रूपरेखाओं पर एक अध्यादेश उत्तर प्रदेश में उद्घोषित किया गया है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

†[ ] English Translation.

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) The matter is essentially for the concerned State Governments. Recently an Ordinance has been promulgated in U.P. to regulate the administration and application of Temple funds etc., on the lines of similar legislations in some Southern States.

(b) No such proposal is under consideration of the Government of India at present

(c) Does not arise.]

तमिलनाडु में सरकारिया आयोग द्वारा की गई जाँच के परिणाम

565. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सरकारिया आयोग द्वारा की गई जांच के कुछ प्रारम्भिक परिणामों के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†[**Findings of enquiry conducted by Sarkaria Commission in Tamil Nadu**

565. SHRI PRAKASH VEER SHASTRI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any information regarding some of the preliminary findings of the enquiry conducted by the Sarkaria Commission in Tamil Nadu has been received; and

(b) if so, what are the details thereof?]

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) सरकारिया जांच आयोग ने जांच की कार्य विधि निर्धारित करने के लिए दिनांक 14 तथा 15 मई, 1976 को दिल्ली में एक बैठक की; और 21 मई, 1976 को आयोग ने अपने द्वारा अन्तिम रूप दी गई जांच की कार्यविधि तथा अन्य क्रियाविधि सम्बन्धी ऐसे मामलों, जो उपर्युक्त सुनवाई के दौरान उसके समक्ष उठाए गए थे, के बारे में अपने आदेश की घोषणा की। सरकारिया आयोग द्वारा तमिलनाडु में कोई बैठक जांच के हेतु नहीं की गई है और अपनी जांच की विषय-सामग्री के सम्बन्ध में आयोग ने कोई निष्कर्ष नहीं दिये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINeSTRATIVE REFORMS (SHRI OM MEHTA): (a) Sarkaria Commission of Inquiry held a sitting at Delhi on 14th and 15th of May, 1976, *inter alia* to devise the procedure for the inquiry, and on 21st May, 1976, the Commission pronounced its order as to the procedure for the inquiry finalised by it, and on other procedural matters which had been raised before it during the course of the hearing referred to above. No inquiry has been conducted by the Sarkaria Commission in Tamil Nadu: and there has been no finding by it on the subject matter of its inquiry yet.

(b) Does not arise]

फिल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन

566. **डा० रामकृपाल सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या फ़िल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ; यदि हां, तो बोर्ड का पुनर्गठन कब तक हो जाने की संभावना है ?

†[**Reorganisation of Board of Film Censors**

566. DR. RAMKRIPAL SINHA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state whther any decision has been taken to reorganise the Board of Film Censors, if so, by when the Board is likely to be reorganised?]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : इससे पहले कि

†[ ] English Translation.